



तापमान 29 - 18
आर्द्रता 70%
सूर्योदय: 5:53 सूर्यास्त: 16:52

स्थानीय खबरें पृष्ठ तीन, चार और पांच पर

कोलकाता, मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष षष्ठी, वि.स. 2081, पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

सुविचार : कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसा से बड़ा होता है।



भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब बरकरार रखा -पृष्ठ 8

ज्यादातर एक्जिट पोल ने महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा गठबंधन को बढ़त का अनुमान जताया

नयी दिल्ली : महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आए ज्यादातर एक्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि 'एक्सिस माई इंडिया' के सर्वेक्षण में झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की सरकार की वापसी का अनुमान जताया गया है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान हुआ, वहीं झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 सीट के लिए वोट डाले गए। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ था। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन 'महायुति' तथा कांग्रेस, शिवसेना (उबाठा) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) के बीच मुकाबला है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) तथा 'इंडिया' गठबंधन के बीच मुकाबला है। राजग में भाजपा, आजसू, जनता दल (यूनाइटेड) तथा लोक जनशक्ति

पार्टी (रामविलास) शामिल है जबकि 'इंडिया' गठबंधन के घटक में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) शामिल है। 'मैट्रिज' के सर्वेक्षण के अनुसार, महायुति को 150-170 तथा एमवीए को 110-130 सीट मिल सकती है। 'लोकशाही मराठी-रूद्र' के सर्वेक्षण में कहा गया है कि महाराष्ट्र में महायुति 128-142 सीट हासिल करके एक बार सत्ता में बरकरार रह सकती है। एमवीए को 125-140 सीट तथा अन्य को 18-23 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। 'पी-मार्क' के एक्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि महायुति को 137-157 तथा एमवीए को 126-146 सीट हासिल हो सकती है। 'पीपुल्स प्लस' के सर्वेक्षण का आकलन है कि महायुति 175-195 सीट हासिल

सर्वे एजेंसी	झारखंड विधानसभा चुनाव			महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव		
	कुल सीटें 81 बहुमत 41			कुल सीटें 288 बहुमत 145		
भारत रिपोटर्स पोल	37-40	36-39	0-2	125-140	135-150	20-25
न्यूज 18-मैट्रिज	42-47	25-30	1-4	150-170	110-130	8-10
P-MARK	31-40	37-47	00	137-157	126-146	2-8
प्राणक्य स्टैटिज	45-50	35-38	3-5	152-160	130-138	6-8
पीपुल्स प्लस	44-53	25-37	5-9	175-195	85-112	7-12
इलेक्टोरल एज	44-53	25-37	5-9	118	150	20
राजद-नाट-ज्वि	40-44	30-40	1	122-186	69-121	12-29
एक्सिस माई इंडिया	25	53	03	137-157	126-146	2-8
सी वोटर्स	36	26	19	128-142	125-140	18-23
पीपुल्स प्लस	33-42	30-39	2-6	127-135	147-155	10-13
लोक पोल				115-128	151-162	6-14
पीपुल्स प्लस				135-157	123-140	10-15

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 60 प्रतिशत मतदान

झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 68 प्रतिशत मतदान हुआ

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 68 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जबकि वित्तीय राजधानी मुंबई में 51.41 प्रतिशत मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में मुंबई में मतदान का आंकड़ा 50.67 प्रतिशत था। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और लोगों ने 1,00,186 बूथ पर 4,100 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया, जो 2019 के चुनाव में बनाए गए बूथ की संख्या से अधिक है। वर्ष 2019 में 96,654 बूथ थे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।



राज्य के इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर राज्य की सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा है। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि ये आंकड़े अस्थायी हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में 61.74 प्रतिशत मतदान हुआ था। नक्सल प्रभावित हड़पथरली जिले में बुधवार को 69.63 प्रतिशत मतदान हुआ,

जबकि वित्तीय राजधानी मुंबई में 51.41 प्रतिशत मतदान हुआ। 2019 के चुनाव में मुंबई में मतदान का आंकड़ा 50.67 प्रतिशत था। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और लोगों ने 1,00,186 बूथ पर 4,100 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया, जो 2019 के चुनाव में बनाए गए बूथ की संख्या से अधिक है। वर्ष 2019 में 96,654 बूथ थे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाये गये: सरकार

नयी दिल्ली : केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार के व्यापक स्तर पर डिजिटलीकरण के प्रयास से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में काफी बदलाव आया है और 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया है। इससे वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए नये मानक स्थापित हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 80.6 करोड़ लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने वाली पीडीएस प्रणाली में सुधार के तहत आधार के जरिये सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने ग्राहक को जाने (ई-केवाईसी) की व्यवस्था से 5.8 करोड़ नकली राशन कार्ड हटाए जा सके हैं। बयान के अनुसार, "इन

प्रयासों के परिणामस्वरूप गड़बड़ी में काफी कमी आई है और लक्षित लोगों तक पहुंच में वृद्धि हुई है।" मंत्रालय के अनुसार, लगभग सभी 20.4 करोड़ राशन कार्ड को डिजिटल कर दिया गया है। इनमें से 99.8 प्रतिशत आधार से जुड़े हैं और 98.7 प्रतिशत लाभार्थियों को पहचान का सत्यापन बायोमेट्रिक माध्यम से किया गया है। बयान के अनुसार, देशभर में उचित मूल्य की दुकानों पर 5.33 लाख ई-पीओएस (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरण लगाये गये हैं। इसके जरिये खाद्यान्न वितरण के दौरान आधार के जरिये सत्यापन करने के साथ यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन का वितरण सही व्यक्ति तक हो।

तलाक याचिका लंबित रहने के दौरान पत्नी ससुराल जैसी सुविधाएं पाने की हकदार: न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि तलाक की याचिका लंबित रहने के दौरान पत्नी को उसी तरह की सुविधाएं पाने का अधिकार है जो उसे ससुराल में मिलती है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने केरल के एक हदयरोग विशेषज्ञ से अलग रह रही उनकी पत्नी को दिए जाने वाले अंतरिम गुजारा भत्ता को बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये प्रति महीने कर दिया। उच्च न्यायालय ने अंतरिम गुजारा भत्ता कम कर दिया था। कुटुम्ब अदालत ने चिकित्सक की पत्नी को 1.75 लाख रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था, वहीं मद्रास उच्च न्यायालय

ने इस राशि को घटाकर 80,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। पीठ ने कहा, "उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी (पति) की आय के संबंध में कुछ पहलुओं की अनदेखी की है जिस पर कुटुम्ब अदालत ने विचार किया था। यह भी संज्ञान में है कि अपीलकर्ता कामकाजी नहीं हैं और उन्होंने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी।" उसने कहा, "अपीलकर्ता अपनी ससुराल में कुछ खास सुविधाओं की अभ्यस्त हो गई थी और इसलिए, तलाक याचिका के लंबित रहने के दौरान, वह उन्हीं सुविधाओं को पाने की हकदार है, जिनका वह अपनी ससुराल में हकदार होती।"

भारत, चीन के रक्षा मंत्रियों ने लाओस में की वार्ता, पारस्परिक विश्वास बहाली के लिए काम करने पर सहमत



नयी दिल्ली : भारत और चीन ने बुधवार को पारस्परिक विश्वास एवं समझ की बहाली के लिए एक रोडमैप की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष दोंग जून के साथ वार्ता के दौरान 2020 के "दुर्भाग्यपूर्ण सीमा संघर्षों" से सीख लेने का आह्वान किया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात लाओस की राजधानी वियेत्तियान में हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले ही भारतीय और चीनी सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में दो अंतिम टकराव स्थलों से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा

में सिंह ने इस बात पर जबर दिया कि भारत और चीन के बीच सीमा संबंधों का वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सोमवार को विदेश मंत्री एस

जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष दोंग जून ने जू-20 शिखर सम्मेलन से इतर रियो डी जेनेरियो में बातचीत की जिसमें भारत-चीन संबंधों में "अगले कदमों" पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करने, सीपी उड्डाण और मीडिया आदान-प्रदान जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि विशेष प्रतिनिधियों और संचय-उपमंत्री तंत्र की बैठक भी शीघ्र ही होगी। सिंह ने दोंग के साथ अपनी बैठक में संघर्ष के बजाय सहयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

अब वक्फ बिल के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी में है ममता सरकार

निंदा प्रस्ताव नहीं बल्कि जवाबी बिल लाने की तैयारी में है तृणमूल

कोलकाता, समाज्ञा : बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। पता चला है कि इस सत्र के दौरान ममता सरकार ने वक्फ बिल के खिलाफ विधानसभा में विधेयक पेश करने की योजना बनाई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की आल-तेचना पहले ही कर चुकी हैं। तृणमूल इसका विरोध शुरू से कर रही है और पार्टी के राज्यसभा में मुख्य सचेतक नदीमूल हक और श्रीरामपुर के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच इस मुद्दे को उठाने जिम्मा सौंपा गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्र द्वारा वक्फ बिल पेश किए जाने पर उसके खिलाफ पहले निंदा प्रस्ताव लाने की चर्चा थी। परंतु,

बदली हुई परिस्थिति में ममता सरकार प्रस्ताव नहीं बल्कि जवाबी विधेयक लाकर केंद्र सरकार को उत्तर देना चाहती है। लिहाजा, इस मसले पर विधानसभा सचिवालय और राज्य के कानून एवं संसदीय विभाग के बीच चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा का सारांश मुख्यमंत्री को भी बता दिया गया है। हालांकि, स्पीकर बिमान बनर्जी ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। पिछले हफ्ते जब उनसे वक्फ मुद्दे पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद ही इस बारे में कुछ कहना संभव होगा। हालांकि, स्पीकर कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन केंद्र के वक्फ बिल के जवाबी बिल को लेकर तृणमूल विधायक दल को हरी

झंडी मिल चुकी है। इसीलिए मामले को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार को शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया जाएगा। सत्ता पक्ष मंगलवार और बुधवार को विधानसभा में संविधान दिवस पर चर्चा का प्रस्ताव लाएगा। चर्चा का दौर खत्म होने के बाद ही राज्य वक्फ से जुड़ा बिल लाएगा। तृणमूल विधायक दल के सूत्रों के मुताबिक, वक्फ बिल विधानसभा में अल्पसंख्यक विधायक पेश कर सकते हैं या नहीं। मामला भाजपा के कानों तक पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा विधायक वक्फ से जुड़े बिल पर चर्चा में हिस्सा लेंगे और केंद्र सरकार के पक्ष में बयान पेश करेंगे।

भारत कैरेबियाई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने को इच्छुक : प्रधानमंत्री मोदी

जॉर्जटाउन (गुयाना) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत कैरेबियाई देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने को इच्छुक है। मोदी बुधवार को गुयाना पहुंचे और कहा कि उनकी यह यात्रा "दोनों देशों के बीच मित्रता को प्रगाढ़ करेगी।" यह 50 साल से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा है। मोदी ने कहा कि भारत-कैरिबियन शिखर सम्मेलन से भारत के साथ कैरेबियाई देशों का आर्थिक सहयोग, कृषि और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, तथा विज्ञान और नवाचार जैसे क्षेत्रों में संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। कैरिबियन (कैरेबियाई समुदाय और साझा



बाजार) एक क्षेत्रीय समूह है। कैरिबियन के शासनाध्यक्षों और प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मुलाकात 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 74वें सत्र से इतर हुई थी, जहां उन्होंने भारत से 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में सहयोग के

Suffering from hip or Knee pain? Ask Dr. Santosh

"Knee replacement can bring you back to normalcy, when done with precision" - Dr Santosh Kumar

प्रश्न- नी-रिप्लेसमेंट सर्जरी के परिणामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
डॉ. संतोष ने बताया कि नी-रिप्लेसमेंट सर्जरी के परिणामों के लिए कई चीजे मायने रखती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्जन की विशेषज्ञता और अनुभव। सर्जन और उनकी टीम का कौशल सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेशक इस्तेमाल किया जाने वाला इम्प्लांट भी अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता का होना चाहिए। लेकिन, मशीन के पीछे उसे चलाने वाला आदमी है, जो ज्यादा मायने रखता है। सर्जरी के बाद अच्छे नर्व ब्लॉक्स और अन्य मल्टी-मॉडलिटी के माध्यम से दर्द नियंत्रण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। सर्जरी के बाद व्यायाम स्वास्थ्य लाभ में तेजी लाता है और उत्साह को बढ़ाता है। इन सबके के साथ मरीज का रवैया भी बहुत महत्वपूर्ण है। मरीज की सकारात्मक सोच उसे ठीक



करने में काफी अहम भूमिका निभाता है।
प्रश्न- नी-रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सबसे अच्छा इम्प्लांट कौन सा है?
डॉ. संतोष ने बताया कि इस्तेमाल किए जाने वाले इम्प्लांट अंतरराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए और लंबे समय तक फॉलोअप करना चाहिए। न्यू इम्प्लांट से बचना चाहिए। हम लंबे जीवन के लिए लो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस फ्लेक्सिबल इम्प्लांट का उपयोग करते हैं। टिबियल प्लेट आमतौर पर टाइटेनियम से बनी होती है। इम्प्लांट के दौरान स्ट्रेस

को संतुलित रखने बहुत जरूरी है। यह अनिवार्य रूप से एक अनुभव सर्जन द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छी सिमेंटेशन तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है जो इम्प्लांट को हड्डी में ठीक करता है, जो फिर से सर्जन को ही निर्भर करता है।

प्रश्न- ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाने की सही उम्र क्या है?
डॉ. संतोष उम्र के अनुसार जब रोजमर्रा के काम करने में परेशानी आने लगे तो उसे, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में देरी करने से सर्जरी अधिक कठिन हो जाती है और रिकवरी में भी देरी होती है। लेकिन हां, जरूरत से पहले ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करवाना भी नहीं चाहिए।

प्रश्न- ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत किसे होती है?
डॉ. संतोष जब किसी व्यक्ति को चलने फिरने में परेशानी आने लगे। घुटनों में दर्द होने का आरश्राइटिस भी एक प्रमुख कारण होता है, और जब ये दर्द दैनिक जीवन की गतिविधियों को

प्रश्न- रिप्लेसमेंट इम्प्लांट कितने सालों तक रहती है?
डॉ. संतोष नी-रिप्लेसमेंट इम्प्लांट ज्यादातर सीमेंटेड होते हैं और औसतन 20 से 30



प्रभावित करना शुरू कर देता है, तो उसे नी-रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है।

साल तक चलने की उम्मीद की जाती है। अनसीमेंटेड हिल इम्प्लांट अधिक समय तक चलता है।

Dr. Santosh Kumar Hip & Knee Foundation

Chamber : Plot No 332, Laketown, Block A, Kolkata-700 089
Belle Vue Clinic- Kolkata ● www.mykneemylife.org ● www.facebook.com / Dr.santoshkumar.orthosurgeon
● WhatsApp : 09831911584 ● Email : santodr@gmail.com
Call for Appointment : 9831911584 / 9831266632 ● Experience of Treating 25000+Patients in 15+Years

